THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PEROLEUM AND CHEMICALS (SHRI K. R. GANESH): It will be possible to estimate the cost of production of crude from Bombay High, only after the full production potential has been assessed and a detailed project report prepared. The expenditure on Bombay High offshore during 1973-74 was Rs. 7.67 crores and expenditure during 1974-75 is estimated at Rs. 13.29 crores. A provision of Rs. 51.10 crores has been made for 1975-76.

Setting up of a Fertilizer Plant in Gujarat

*493. SHRI VEKARIA:
SHRI D. P. JADEJA:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to instal a fertilizer plant in Gujarat State during the next Five Year Plan; and

(b) if so, where and the broad features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI K. R. GANESH): (a) and (b). A letter of intent has been issued to the Gujarat State Fertilizer Company, Baroda for creation of additional capacity during the 5th Plan period for production of 5,28,000 tonnes of urea. The programme for setting up of additional fertilizer capacity during the Sixth Plan period has not yet been drawn up.

उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये धनराशि

*494. श्री बनमाली बाबू : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उर्वरक कारखाने स्थापित करने की वर्तमान योजनायें क्या हैं ;

(ख) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है; और

(ग) उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये धन एकत्र करने हेतु और क्या साधन जुटाये जा रहे है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). इस समय 19.81 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता के 18 उर्वरक कारखाने (11 सरकारी क्षेत्र मे और 7 गैर सरकारी क्षेत्र में, चालू है। 7.8 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता की 5 परियोजनायें (2 सरकारी, 2 गैर-सरकारी और 1 सहकारी क्षेत्रीय) कार्यान्वित की अग्रिम अवस्थाओं मे है, जिन से कुल क्षमता 27.61 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन हो जायेगी। इस में इस्पात सयत्रों में उत्पादों के रूप में निर्मित उर्वरक भी शामिल है। फास्फेटिक उर्वरक के लिये पहले से विकसित अथवा उन परियोजनाओं, जो कि मुकम्मल होने वाली हैं, में विकसित की जाने वाली क्षमता पी2ओ5 के रूप में 8.6 लाख मीटरी टन हो जायेगी।

इन के अतिरिक्त, 14 परियोजनाएं कार्यान्वित की विभिन्न अवस्थाओं मे है और 10 अन्य परियोजनाओं को सिद्धांत रूप में मंजूरी/अनुमति दे दी गई है। इन सभी परियोजनाओं के मुकम्मल हो जाने से, कुल क्षमता के 65 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 17.82 लाख मीटरी टन पी2ओ5 हो जाने की आशा है, जिसका विवरण इस प्रकार है —

(लाख टनों में)

	सरकारी क्षेत्र		गैर सरकारी क्षेत्र		सरकारी/संयुक्त क्षेत्र	
	नाइट्रोजन (एन)	पी 2 ओ 5	नाइट्रोजन (एन)	पी 2 ओ 5	नाइट्रोजन (एन)	पी 2 ओ 5
(1) चालू यूनिट . .	11.28	2 02	8.53	3 58	—	—
(2) परियोजना, जो मुकम्मल होने वाली है . .	3.04	0.90	2.61	0.82	2.15	1.27
(3) कार्यान्वयनाधीन अन्य परियोजनाए	15.36	4.58	1.60	—	—	—
(4) अनुमोदित/सिद्धान्त रूप मे अनुमोदित परियोजनाए	9.45	3.00	5 73	0 82	5.22	0.83
कुल .	39 13	10 50	18 47	5 22	7.37	2.10

कुल एन (39 13+18 47+7 37) = 64.97 लाख मीटरी टन अथवा 65.00

कुल पी 2 ओ 5 (10.50+5.22+2.1) = 17.82 लाख मीटरी टन

एक महत्वपूर्ण उद्योग होने के नाते, उर्वरक परियोजनाओं की संसाधनों के आवटन में समुचित प्राथमिकता दी जाती है । रुपया ससाधनों के बारे मे, सरकारी क्षेत्र मे स्थापित की जाने वाली नईपारी योजनाओं के लिये पाचवी योजना के प्रारूप मे 560 करोड रुपये का आवटन निहित है । गैर-सरकारी तथा सहकारी/संयुक्त क्षेत्रों की परियोजनाओ के लिये, सम्बन्धित उद्यमकर्ताओं को आवश्यक समोधन अपने आप जुटाने होंगे ।

रुपया ससाधनो के अलावा, उर्वरक परियोजनाओ की उन सामग्रियों तथा सेवाओं, जो देश में उपलब्ध नही हैं, के लिये विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी । यदि यहां भी, उचित ऋणों अथवा निर्बाध विदेशी मुद्रा जैसा कि उपयुक्त हो, के आवटन मे सभी परियोजनाओं को समुचित प्राथमिकता दी जाती है ।

रतलाम डिवीजन में कोयले की कमी का माल गाड़ियों के चलने पर प्रभाव

*495. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में कोयले की कमी के कारण अनेक मालगाड़ियां नियमित रूप से नहीं चल पाई हैं ;

(ख) क्या इसके कारण जावरा, मंदसौर और नीमच में रेलवे बुकिंग पर विपरीत प्रभाव पडा है । तथा इसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से रेलवे को वित्तीय हानि हुई है; और

(ग) कोयले की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?